नईदुनिया

संपादकीय

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सार्थक पहल

ऐसे वक्त में जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश दुख और गुस्से की मन:स्थिति से गुजर रहा है, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का एक सशक्त संदेश दिया है। जो कि वक्त की जरूरत भी थी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन ने सर्वसम्मति से इस वीभत्स हत्याकांड की पुरजोर निंदा करते हुए बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया। जिस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लोगों को आक्रोशित तथा दुखी किया, उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना व निंदा प्रस्ताव पारित करना निश्चित रूप से देश के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा ही है। निश्चय ही यह संदेश देश की गंगा-जमुनी संस्कृति के अनुरूप ही है। निर्विवाद रूप से आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हर धर्म के व्यक्ति को खुले मन से आतंकियों की निंदा करनी चाहिए। यह विडंबना ही है कि यह भयावह घटना राज्य से केंद्रशासित बने जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण और सक्रिय भागीदारी वाले विधानसभा चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के छह माह बाद हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिये सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पुनरुद्धार से होने वाले लाभ यूं ही व्यर्थ न चले जाएं। यह सकारात्मक संदेश ही है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने आतंक को सिरे से खारिज किया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नरसंहार के बाद घाटी के लोगों के दिलों से सीधे निकल रहे आक्रोश और दुख को कश्मीर के लिये एक उम्मीद की किरण के रूप में देखते हैं। जो पाक पोषित आतंकवाद को नकारने जैसा ही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा भी कि इस केंद्रशासित प्रदेश की हर मस्जिद में पहलगाम हमले में मारे लोगों की याद में मौन रखा गया। जो यह बताता है कि धर्म-संप्रदाय से परे लोग पूरे देश की संवेदनाओं को महसूस करते हैं। साथ ही आतंकवाद को सिरे से खारिज भी करते हैं।

निश्चित रूप से इस नये कश्मीर से आया यह संकेत दिल को छूने वाला है। जो यह भी बताता है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता, करुणा और लचीलेपन की यह भावना स्वागत योग्य है। साथ ही यह भी उम्मीद जगी है कि यह नई सोच विघटनकारी ताकतों का मुकाबला कर सकती है। उन अलगाववादियों का जो विकासशील जम्मू-कश्मीर को फिर से 1990 के दशक की शुरुआत के बुरे दौर में धकेलना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री होने के नाते उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया किया है कि वे राज्य में आये पर्यटकों को सुरक्षित घर वापस भेजने की अपनी जिम्मेदारी में विफल रहे हैं। उन्होंने उन कयासों को खारिज किया कि त्रासदी का उपयोग राजनीतिक लाभ हेतु राज्य का दर्जा पाने के लिये किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आतंकवाद अपना भयानक रूप दिखाता रहेगा, तब तक जम्मू-कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा समाप्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कश्मीरियों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की पूरी तरह से भागीदारी जमीन पर एक स्पष्ट अंतर ला सकती है। हालांकि, बहुत कुछ केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा संकटग्रस्त केंद्रशासित प्रदेश को दिए जाने वाले समर्थन पर निर्भर करेगा। निस्संदेह, आतंकवाद के इस विनाशकारी आघात के बाद जम्मू-कश्मीर को संभालने में मदद करना राष्ट्रीय प्राथमिकता बननी चाहिए। निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर विधानसभा से आया यह रचनात्मक संदेश देश की एकता व अखंडता के लिये सुखद ही है। देश में आतंकवाद की इस घटना के बाद जैसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की कोशिशें की जाती रही है, उसको यह सार्थक जवाब है। जो वक्त की मांग भी थी। घाटी से संदेश आया है कि यहां लोग देश की संवेदना से उसी तरह के सरोकार रखते हैं, जैसा कि अन्य राज्यों के लोग रखते हैं। यह भी कि आतंकवाद किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

मजदूरों के महत्व को दर्शाता मजदूर दिवस

मजदूर दिवस 1 मई पर विशेष

रमेश सर्राफ धमोरा

मजदूर दिवस मजदूरों के महत्व को दर्शाने का महत्वपूर्ण उत्सव है। भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उस दिन मजदूरों की भलाई के लिए काम करने व मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना होता है। मगर ऐसा हो नहीं पाया है। भारत में 90 फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनको सभी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। देश में श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित व असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा है।

भारत में एक मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में एक मई 1923 को मद्रास दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारती मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने शुरू की थी। मद्रास हाई कोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक संकल्प पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाये और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाये। वर्तमान में भारत समेत लगभग 80 देशों में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है।

मजदूर दिवस दुनिया के सभी कामगारों, श्रमिकों को समर्पित होता है। इस बार के अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क की थीम है। स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलाइजेशन की भूमिका। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कार्यस्थल को और ज्यादा सुरक्षित और सेहतमंद बनाने में किया जाएगा। स्मार्ट हेलमेट्स, सेफ्टी सेंसर, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम ये सब भविष्य की सुरक्षा के अहम हिस्से बनेंगे। यह थीम हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हम तकनीक का सही इस्तेमाल करते हुए कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित कर सकें।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने का प्रमुख भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ही होता है। मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर राष्ट्र तरक्की करता है, लेकिन भारत का श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक तबके में अब कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी मजदूरों के उत्साह को कम कर दिया है। अब मजदूर दिवस इनके लिए सिर्फ कागजी रस्म बनकर रह गया है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है। उद्योगपति खुद को मालिक समझने की बजाय अपने-आप को ट्रस्टी समझें मगर ऐसा होता नहीं है। इसी कारण भारत में मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी अपने समय में किसानों, मजदूरों और कामगारों के हक में आवाज उठाई थी। गुरु नानक देव जी ने काम करना, नाम जपना, बांट छकना और दसवंध निकालने का संदेश दिया था। गरीब मजदूर और कामगार का विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए मनमुख से गुरमुख तक की यात्रा करने का संदेश दिया था।

सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां मजदूरों की स्थिति में सुधार हो पाया है। दुनिया के सभी देशों की सरकार मजदूरों के हित के लिए बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करती हैं मगर जब उनकी भलाई के लिए कुछ करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाती हैं। इसीलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। हमारे देश के मजदूरों को न तो मालिकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और ना ही अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जहां ना उनके रहने की कोई सही व्यवस्था होती है न ही उनको कोई ढंग का काम मिल पाता है। मगर आर्थिक कमजोरी के चलते शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग जैसे तैसे कर वहां अपना गुजर-बसर करते हैं।

बड़े शहरों में झोंपड़पट्टी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां रहने वाले लोगों को कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करता है। इसको देखने की न तो सरकार को फुर्सत है ना हीं किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को शौचालय जाने के लिए भी घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। झोपड़पट्टी बस्तियों में ना रोशनी की सुविधा रहती है। ना पीने को साफ पानी मिलता है और ना ही स्वच्छ वातावरण। शहर के किसी गंदे नाले के आसपास बसने वाली झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब तबके के मजदूर कैसा नारकीय जीवन गुजारते हैं। उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मगर इसको अपनी नियति मान कर पूरी मेहनत से अपने मालिकों के यहां काम करने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों के मन में जरा भी सहानुभूति के भाव नहीं रहते हैं। उनसे 12-12 घंटे लगातार काम करवाया जाता है। घंटों धूप में खड़े रहकर बड़ी-बड़ी कोठियां बनाने वाले मजदूरों को एक छप्पर तक नसीब नहीं हो पाता है।

देश के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर हर वक्त इस बात की तलवार लटकती रहती है कि ना जाने कब मालिक उनकी छंटनी कर काम से हटा दे। कारखानों में कार्यरत मजदूरों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है। मजबूरी में मजदूर कारखाने के मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। कारखानों में श्रम विभाग के मापदण्डो के अनुसार किसी भी तरह की कोई सुविधायें नहीं दी जाती है।

कई कारखानों में तो मजदूरों से खतरनाक काम करवाया जाता है जिस कारण उनको कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है। कारखानों में मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, पीने का साफ पानी, विश्राम की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवायी जाती है। मालिकों द्वारा निरंतर मजदूरों का शोषण किया जाता है। मगर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये बनी मजदूर यूनियनो को मजदूरों की बजाय मालिको की ज्यादा चिंता रहती है। हालांकि कुछ मजदूर यूनियनें अपना फर्ज भी निभाती हैं मगर उनकी संख्या कम है। हर बार मजदूर दिवस के अवसर पर सरकारें मजदूरों के हित की योजनाओं के बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करती हैं। जिनमें मजदूरों के हितों की बहुत सी बातें लिखी होती हैं किन्तु उनमें से अमल किसी बात पर नहीं हो पाता है।

वैश्विक शांति के लिए विकसित भारत की अवधारणा

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

हम सिर्फ आर्थिक स्तर बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी या किसी अन्य आर्थिक मीट्रिक के संदर्भ में आर्थिक विकास व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालकर समाज को कमजोर करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो अंततः समाज और राष्ट्र को कमजोर करेगा। जब हम दुनिया की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि शराब, कई रूपों में नशीले पदार्थ, दवाइयां और चिकित्सा आवश्यकताएं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण और प्राकृतिक आवासों का विनाश, सभी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि राष्ट्र को इन अप्राकृतिक, अनैतिक कार्यों के परिणामस्वरूप अधिक धन प्राप्त होता है, तो ऐसा जीडीपी सराहनीय नहीं है।

भौतिकवादी दुनिया ने विकास, खुशी, प्राकृतिक अवलोकन, रिश्तों, देखभाल, अपनापन और सामाजिक संबंधों के आयामों को बदल दिया है। हालाँकि दुनिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान के उपयोग के माध्यम से जीवन के हर भौतिक क्षेत्र में तेज़ी से विस्तार कर रही है, जो सराहनीय है लेकिन क्या हम वास्तव में खुश, आनंदित, प्रकृति के प्रति जागरूक और वास्तव में सही जीवन जी रहे हैं या हमने अपने जीवन को मशीनीकृत कर दिया है, प्रेम, बंधन और सामाजिक आदर्शों को भूल गए हैं। हम 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल मनाएंगे; हमें आने वाले दशकों में भारत को फिर से महान बनाने के लिए कैसे प्रयास और ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शांति, आनंद और बढ़ी हुई सामाजिक आर्थिक ताकत के साथ? आइए देखें कि हम इस शानदार राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं।

भारत को महाशक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए : जब हमने अमृत काल में प्रवेश किया और 2047 तक भारत के विश्वगुरु बनने की कामना की। इसका क्या मतलब है? क्या यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या चीन जैसी महाशक्ति को संदर्भित करता है? बिल्कुल नहीं। हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते, जिसका अर्थ है अहंकार, लालच, अनैतिकता, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष और युद्ध की संस्कृति, आर्थिक अनियमितताएं इत्यादि। तो, 2047 में भारत कैसा दिखना चाहिए, जब हमारे पास 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी रक्षा सेना और विशाल कार्यबल होगा?

विश्वगुरु का वास्तव में क्या अर्थ है?

हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र का विकास करे। राष्ट्रीय लोकाचार और राष्ट्र-प्रथम मानसिकता स्वार्थी व्यवहार पर वरीयता लेगी। जब ऐसी मानसिकता विकसित होती है तो मजबूत सामाजिक बंधन वाला राष्ट्र बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रगति का अनुभव करता है, साथ ही पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन भी करता है। जब ऐसा विश्व दृष्टिकोण उभरता है तो न केवल व्यक्ति, समाज और राष्ट्र समृद्ध हो सकते हैं बल्कि संपूर्ण विश्व सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होता है। किसी भी राष्ट्र का स्वार्थी कारणों से शोषण या वर्चस्व नहीं किया जाएगा; इसके बजाय, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को राष्ट्र निर्माण के सभी पहलुओं में प्रोत्साहित किया जाएगा। यही विश्वगुरु का सही अर्थ है। हम जीवंत राष्ट्र इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जहाँ हिंसा, अपराध, अन्याय, घृणा और असमानता सभी समाज का हिस्सा हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसे इस तरह से कहाकि हम एक राष्ट्र हैं, देश नहीं और हम अतीत के जीवंत उदाहरण रहे हैं। अगर हम अपने ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करें तो हम एक जीवंत राष्ट्र के रूप में अपनी महान विरासत को जान पाएंगे। जब नागरिकों में यह मानसिकता जागृत होती है तो लोग और समाज सद्भाव से रहते हैं, जीवन जीने का बंधन बनाते हैं और एक साथ बाधाओं को पार करते हैं, खुशी बढ़ती है। हम सिर्फ आर्थिक स्तर बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी या किसी अन्य आर्थिक मीट्रिक के संदर्भ में आर्थिक विकास व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालकर समाज को कमजोर करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो अंततः समाज और राष्ट्र को कमजोर करेगा। जब हम दुनिया की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि शराब, कई रूपों में नशीले पदार्थ, दवाइयां और चिकित्सा आवश्यकताएं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण और प्राकृतिक आवासों का विनाश, सभी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि राष्ट्र को इन अप्राकृतिक, अनैतिक कार्यों के परिणामस्वरूप अधिक धन प्राप्त होता है, तो ऐसा जीडीपी सराहनीय नहीं है। भारत राष्ट्र के रूप में हमें यह सोचना चाहिए कि हम सनातन धर्म के सिद्धांतों को आधार बनाकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य के मामले में एक स्वस्थ व्यक्ति और समाज बनाने के लिए काम करेंगे। हमें ऐसे किसी भी आर्थिक विस्तार को त्याग देना चाहिए जो व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो। याद रखें कि एक कमजोर समाज एक कमजोर राष्ट्र को जन्म देता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया को आर्थिक ताकत दिखाने के लिए व्यक्तिगत या सामाजिक स्वास्थ्य का त्याग न करें। सनातन धर्म जीवन के सभी पहलुओं में जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। वास्तविक जीवन में सनातन सिद्धांतों का ज्ञान और कार्यान्वयन जीवन कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे समाज और राष्ट्र की मजबूती में योगदान मिलता है।

उज्ज्वल भविष्य के लिए आत्मनिर्भर भारत : आत्मनिर्भरता राष्ट्र को मजबूत बनाने की कुंजी है। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर पैदा करने, उद्यमियों को आगे बढ़ाने, वैश्विक बाजारों का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और कौशल और ज्ञान का निर्माण करके राष्ट्र को लाभ होता है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की और हम राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में इसके परिणाम देख रहे हैं। सरकारों, उद्योगपतियों और समाज को सेमीकंडक्टर, रक्षा, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि उपज, खाद्य प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल दुनिया और पर्यावरण प्रबंधन सहित हर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना हासिल की जानी चाहिए।

आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान और विकास : कोई भी राष्ट्र सामाजिक-आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो सकता है यदि वह अनुसंधान और विकास, नवीन विचारों और रचनात्मकता के लिए पर्याप्त संसाधन समर्पित नहीं करता है। अनुसंधान किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आधार का काम करता है। भारत में अनुसंधान और नवाचार का एक लंबा इतिहास है, ऋषि कणाद, भास्कराचार्य द्वितीय और आचार्य सुश्रुत, सूची लंबी है लेकिन जब मुगलों और फिर अंग्रेजों ने हम पर आक्रमण किया, तो हमने अपना अनुसंधान-उन्मुख दृष्टिकोण खो दिया और मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। इस दृष्टिकोण में मोदी सरकार के प्रयास कई क्षेत्रों में शानदार परिणाम दे रहे हैं, जिनमें स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, विशेष रूप से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचारों में। रक्षा, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और कृषि सभी को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आजकल

आखिर कब थमेगा आतंक का सिलसिला ?

यह गंभीर चिंता का विषय है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों पर विराम नहीं लग पाया है। पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसकी निंदा की है। उस हमले में छब्बीस लोग मारे गए। इसकी प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। पूरे कश्मीर ने इस घटना के विरोध में बंद रखा और आतंकवाद के खिलाफ जगह-जगह जुलूस निकाले गए। इसके बावजूद घाटी में अगर आतंकवादियों के मंसूबे कमजोर नहीं पड़े हैं, तो स्वाभाविक ही सुरक्षा इंतजाम को लेकर फिर से सवाल सिर उठाने लगे हैं। गौरतलब है कि कुपवाड़ा में संदिग्ध आतंकवादियों ने एक समाजसेवक के घर में घुस कर उसे गोली मार दी। छिपी बात नहीं है कि घाटी में आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि वह बार-बार अपने को पाक-साफ साबित करने की कोशिश करता है, भारत के प्रति सहयोग का दिखावा भी करता है, पर दुनिया की नजरों से उसकी हकीकत छिपी नहीं है। पहलगाम के बाद कुपवाड़ा में इस तरह घर में घुस कर हमला करने के पीछे दहशतगर्दों की मंशा साफ है। वे संदेश देना चाहते हैं कि उनके मंसूबे कमजोर नहीं पड़े हैं।

मगर सवाल है कि वहां तैनात खुफिया एजंसियों और सुरक्षा बलों से क्यों और कैसे चूक हो रही है कि वे आतंकवादियों की साजिशों को समय रहते समझ नहीं पा रहे। पहलगाम हमले के पीछे बड़ा कारण सुरक्षा इंतजाम में घोर लापरवाही थी। इसके लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक में अफसोस भी जताया और इसे तुरंत दुरुस्त कर लेने का आश्वासन दिया। इस वक्त वहां राष्ट्रीय सुरक्षा एजंसी घटना की जांच में जुटी है। पूरी घाटी में सुरक्षाबलों की संख्या बढ़ा दी गई है। खुफिया एजंसियां चौकस हैं। इसके बावजूद अगर आतंकी किसी घर में घुस कर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं, तो स्वाभाविक ही आतंकवाद से लड़ने संबंधी हमारी तैयारियों पर अंगुलियां उठेंगी। नौ वर्ष पहले नोटबंदी हुई, तो दावा किया गया था कि इससे आतंकियों की कमर टूट जाएगी। फिर अनुछेद तीन सौ सत्तर खत्म करने के बाद भी लगातार कहा जाता रहा कि घाटी में आतंकवाद लगभग अपने अंतिम दौर में है। मगर हकीकत यह है कि इस अवधि में कई बड़ी आतंकी घटनाएं हो गईं, जिसकी ताजा कड़ी पहलगाम की घटना थी। अच्छी बात है कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक कारगर तरीके पर विचार कर रही है। मगर अब तक के अनुभवों से जाहिर है कि आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की कोई भी रणनीति अब तक कारगर साबित नहीं हो पाई है। पहलगाम हमले के बाद आम जनभावना यही है कि दहशतगर्दी को पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाया जाए।

कैसे राफेल-मरीन सौदा साबित होगा गेम-चेंजर

अजय बनर्जी

भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल-मरीन नौसैनिक लड़ाकू विमानों को लेकर हुआ अंतर-सरकारी समझौता केवल एक सामान्य सैन्य खरीद नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से एक बड़ा कदम है, जो दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

इस समझौते में न केवल विमान की खरीद शामिल है, बल्कि इसमें भारत में निर्मित मिसाइलों के एकीकरण के लिए तकनीक हस्तांतरण का प्रावधान भी है। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में जेट के ढांचे के कुछ हिस्सों के निर्माण के लिए उत्पादन इकाई स्थापित करेगी, साथ ही इंजन, सेंसर और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों के रखरखाव के लिए विशेष केंद्र भी बनाएगी। इससे भारत की विमानन क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को नया बल मिलेगा।

राफेल-मरीन की खासियतें: राफेल-मरीन 1,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है और यह विमानवाहक पोत के डेक से उड़ान भरने और वहीं उतरने में सक्षम है। इसका प्रभावी युद्ध क्षेत्र पोत की समुद्री तैनाती पर निर्भर करेगा। इसमें अत्याधुनिक सेंसर

लगे हैं और यह लंबी दूरी की मेटिओर मिसाइल के साथ-साथ माइका मिसाइल से भी लैस होगा, जो न केवल विजुअल रेंज से बाहर दुश्मन को भेद सकती है, बल्कि आत्मरक्षा में भी कारगर है।

यह विमान हैमर नामक सटीक स्ट्राइक वेपन और लंबी दूरी की स्टैंड-ऑफ मिसाइल स्कैल्प भी ले जा सकता है। विमानवाहक पोत पर उतरने के लिए इसके लैंडिंग गियर को विशेष रूप से मजबूत बनाया गया है, क्योंकि ऐसे पोतों पर लंबी रनवे सुविधा नहीं होती। इसे विशेष पाइलन द्वारा रोका जाता है।

जैसे भारतीय नौसेना के मौजूदा स्ब्द्धत्र-29ग्र विमानों में फोल्डिंग विंग्स की सुविधा है, वैसे ही राफेल-मरीन में भी पंख मोड़ने की व्यवस्था होगी, जिससे हैंगर में अधिक विमान समाहित किए जा सकेंगे। प्रत्येक पंख का लगभग 25त्न हिस्सा मोड़ा जा सकता है।

भारत को क्या लाभ मिलेगा? राफेल-मरीन और भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों की प्रणाली लगभग एक जैसी है। इससे प्रशिक्षण, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स में समन्वय और लागत में कमी आएगी।

सौदे में हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स, सहायक उपकरण, क्रू प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहयोग भी शामिल हैं। आईजीए के तहत भारत में स्वदेशी हथियारों को राफेल-मरीन में एकीकृत करने के लिए तकनीक हस्तांतरण भी किया जाएगा।

इसमें भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को भी शामिल किया जाएगा, जो पहले ही भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई में प्रयोग की जा चुकी है। यह कदम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को बढ़ावा देगा। इस सौदे में भारतीय वायुसेना के मौजूदा 36 राफेल विमानों के लिए अतिरिक्त उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है।